including Deptt. of Agriculture & Cooperation.

Only posts without incumbent are considered for encadrement into IES as per rules/instruction/advice given by DOPT.

केनरा बैंक

193. **श्री रामजीलाल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अगस्त, 1998 के राष्ट्रीय सहारा में "कनाट प्लेस में केनरा बैंक की शाखा का ताला खुला मिला" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार पाए गए और उनके विरुद्ध कब तथा क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केनरा बैंक की दिल्ली स्थित ओवरसीज शाखा में चोरी की घटना 29 अगस्त, 1998 को सायं और 30 अगस्त, 1998 की सायं के बीच हुई। बताया गया है कि मुख्य दरवाजे का ताला काटकर व तोड़कर कुछ चोरों ने शाखा-परिसर में प्रवेश किया और सात कम्प्यूटरों में फेरबदल करने के बाद उनके हार्ड-डिस्क और मैमोरी-चिप्स को लेकर चम्पत हो गए। तथापि इन पी सी यूनिटों/डिस्कों में कोई आंकड़े नहीं थे क्योंकि ये पी०सी० केवल टर्मिनल के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे थे। कुछ फलापियां और मेजों के कुछ दराजों के तालों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। कम्प्यूटर अवयवों की चोरी की अनुमानित हानि लगभग एक लाख रुपए है। बैंक की शिकायत पुलिस के पास 30 अगस्त, 1998 को करवाई गई। पुलिस ने आई पी सी की धारा 457/380 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया है किन्तु अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

Special Fiscal benefits for the North East

194. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the types of special fiscal benefits enlisted in the special industrial policy declared by Government for the North East;

(b) whether a formal notification awarding these benefits from the department of finance have already been made;

(c) if not, the time by which these are proposed to be regularised; and

(d) the special arrangement proposed to be made by Government to promote production through self employment programmes through North Eastern Development Finance Corporation as its nodal agency?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) A new industrial policy for the North East was announced in December, 1997. The salient features of the Policy are:

1. Entire expenditure on Growth Centres, upto Rs. 15 crores would be met through central assistance.
2. Funding pattern for Integrated Infrastructure Development (IID) Centres chagned to 4:1 between Govt. of India and SIDBI.
3. Trsnsport subsidy scheme extended upto 31.3.2007 and amount to be disbursed through NEDFC.
4. Growth Centres & IIDCs become tax free zones for income-tax and excise for 10 years and 15% subsidy on plant & machinery subject to a ceiling of Rs. 30 lakhs.
5. An inerest subsidy of 3% on working capital loans would be provided for a period of ten years after the commencement of production.
6. Comprehensive Insurance scheme for new industrial units.

(b) and (c) The Finance Act, 1997 provided tax holiday for initial 7 years in case of undertaking which begin commercial production of mineral oil in NE Region w.e.f. 1.4.1998. In case of industrial undertaking located in